

पहले मुख्य समाचार।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से महिला आरक्षण से जुड़े ऐतिहासिक कानून को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। कहा- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नारी शक्ति का अधिकार।
- संसद के विस्तारित बजट सत्र का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान के एक सौ इकतीसवां संशोधन विधेयक दो हजार छब्बीस सहित लोकसभा में पेश किए गए तीन विधेयक।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों का किया उद्घाटन। कहा- समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग और सुविधाओं से बना प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल।
- उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति लागू। एकीकृत कंट्रोल रूम के जरिये एआई कैमरों से होगी रियल-टाइम निगरानी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश की पचास प्रतिशत आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नीति निर्माण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग है। श्री मोदी ने कल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान ये बात कही।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी अहंकारपूर्ण भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे भारत की महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, बल्कि यह उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि समूची राजनीतिक व्यवस्था दशकों से इस अधिकार को महिलाओं से छीनने की सामूहिक रूप से दोषी है और इसलिए यह विधेयक प्रायश्चित्त का एक आवश्यक उपाय है।

प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की।

मैं कहता हूँ, अगर हम सब साथ में जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि यह किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत केवल बुनियादी ढांचे, रेलवे या आर्थिक संकेतकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है।

विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, यह समय की मांग है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल संख्या की बात नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि लगभग छह हजार सात सौ ब्लॉक पंचायतों में से लगभग दो हजार सात सौ पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।

चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में कमी आने की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज कर दिया।

इससे पहले, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान का एक सौ इकतीसवां संशोधन विधेयक-दो हजार छब्बीस और परिसीमन विधेयक- दो हजार छब्बीस पेश किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक- दो हजार छब्बीस पेश किया। एक रिपोर्ट-

संसद के विस्तारित बजट सत्र का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया। लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए गए। जिनमें संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों का मकसद नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर पूरी की गई परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को लागू करना है। वर्ष 2023 में संविधान 106 संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत, लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। आनंद कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे सरल बनाया जाना चाहिए और परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण लोकसभा की मौजूदा पांच सौ तैतालिस सीटों पर आधारित होना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एक रिपोर्ट-

यूजीसी ने कहा कि इन पहलों से लैंगिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के महत्व पर सार्थक संवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अधिनियम को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान नारी का अभिनंदन, सशक्त नारी और समृद्ध लोकतंत्र के नारे लगाए गए। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी एक विशाल पदयात्रा का आयोजन कर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। बलिया से विनय कुमार और जौनपुर से राहुल यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

महिला आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में आधी आबादी में उत्साह का माहौल है। जौनपुर में महिला शिक्षक ऋचा दुबे ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव बताया।

यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका उद्देश्य लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना है। इससे देश और समाज में महिलाओं की भागीदारी ही बढ़ेगी। इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा और इस महिला आरक्षण विधेयक से समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी के कारण प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल और सुशासन का बेहतरीन मॉडल खड़ा हुआ है। श्री योगी ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन करते हुए कहा कि सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त होती है।

जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी और यही कार्य की गति जो सुरक्षा पर ध्यान देकर के समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग, समय पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई। परिणाम है सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और उस सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही प्रदेश के अंदर सुशासन का एक मॉडल खड़ा किया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल विहीन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने कई सख्त कदम उठाए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने कल बताया कि आगामी परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह लागू किया जाएगा, जिससे शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए आयोग मुख्यालय में अत्याधुनिक एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की जाएगी। इस कंट्रोल रूम में दो दर्जन से अधिक हार्ड-क्वालिटी स्क्रीन और एआई कैमरों की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान-सीएसआईआर में आयोजित ग्रीष्मकालीन पादप विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह में कल भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गगनयान मिशन की तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा की।

फाइनल ह्यूमन मिशन से पहले हमें कुछ टेस्ट मिशन करने हैं, अभी एक आईडीटी ड्रॉप टेस्ट हुआ है तो आप देख रहे प्रोग्रेस हो रही है बट इवेंचुअली फर्स्ट जीवन मिशन जब होगा वह एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस जर्नी में।

मथुरा के वृन्दावन में यमुना नदी में दस अप्रैल को हुए नाव हादसे में मृतको की संख्या बढ़कर सोलह हो गयी है। बचाव दल को कल यमुना में डूबने वाले एक अन्य श्रद्धालु का शव मिल गया। इसके साथ ही वहां चलाया जा रहा तलाशी अभियान भी समाप्त हो गया।
